Shikshan Sanshodhan : Journal of Arts, Humanities and Social Sciences ISSN(o): 2581-6241
Monthly, Peer-Reviewed, Refereed, Indexed Journal Impact Factor: 9.134
Volume - 9, Issue - 6, June - 2026

DOIs:10.2018/SS/202606002 --:-- Research Paper / Article / Review

भारत में ई-गवर्नेंस : आधुनिक शासन व्यवस्था

[1] सुदेश कलाम, [2] डॉ.मीनाक्षी पंचाल
[2] शोधार्थी, अर्थशास्त्र विभाग, PAHER विश्वविद्यालय (उदयपुर)
[2] Supervisor, अर्थशास्त्र विभाग, (PCSSH), PAHER विश्वविद्यालय (उदयपुर)
sudeshkalam@gmail.com, meenakshimlsu@gmail.com

सारांशः ई- गवर्नेंस की उत्पत्ति 20 वी. सदी के अंतिम दशकों में हुई जब सुचना एवं संचार प्रोद्योगिकी का उपयोग सरकारी कामकाज में किया जाता था। इसकी व्यवस्थित शुरूआत वर्ष 1989 में विश्व बैंक द्वारा की गई और अन्य देशो द्वारा बाद में अपना लिया गया। विकासशील देशों उदारीकरण व विकास की नीतियां इस स्थिति में सफल हो सकती है जब इन देशों में ई-गवर्नेंस की शुरूआत हो। भारत में ई-गवर्नेंस की औपचारिक शुरूआत वर्ष 1970 के दशक में हुई। आज इंटरनेट के माध्यम से पूरा देश एक हो रहा है। 2015 में शुरू हुए 'डिजिटल इंडिया अभियान' में ई-गवर्नेंस को एक नई दिशा प्रदान की है, सरकार की इस पहल का उद्धेश्य नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और सेवाओं को इंटरनेट और मोबाइल फोन के माध्यम से सरल बनाना है। ई-गवर्नेंस आधुनिक प्रशासनिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। भारत में डिजिटल इंडिया अभियान, आधार, डिजिलॉकर, ऑनलाइन भुगतान तथा भूमि रिकार्ड डिजिटलीकरण जैसी योजनाओं के शासन प्रणाली को अधिक सुलभ बनाया है। इस शोध पत्र में ई-गवर्नेंस की अवधारणा, उद्देश्य, लाभ तथा चुनौतियों जैसे बिन्दुओं को बतलाया जाएगा।

मुख्य शब्दः- ई-गवर्नेंस, डिजिटल इण्डिया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रशासन, सुशासन।

1. प्रस्तावनाः-

ई-गवर्नेंस व्यवस्था पूरे विश्व में शासन प्रणाली की एक नवीन पद्धति है। वर्तमान में कुछ दशकों से विश्व के कई देशों ने ई-गवर्नेंस शासन प्रणाली को अपनाया है। ई-गवर्नेंस तकनीक को लागू करने का मूख्य कारण शासन व्यवस्था को और अधिक कुशल बनाना है। इस तकनीक के माध्यम से नागरिकों द्वारा सूचना एवं सेवाओं को पहले से अधिक तीव्र गति से तथा कम मूल्य पर प्राप्त किया जा सकता है। यह पद्धति राजनतिज्ञ, लोक प्रशासन अधिकारियों एवं जनता के मध्य पारदर्शी संबंधों की स्थापना करने में सहयोग देती है। इससे जनता को अपनी सरकार के कार्य, सेवाओं एवं प्रदर्शन के संबंध में विस्तृत जानकारी बहुत ही कम समय में प्राप्त होती है। ई-गवर्नेंस प्रशासन प्रणाली द्वारा सरकार अपने नागरिकों को विशिष्ट एवं उत्तम सेवाएं भी प्रदान करती है। व्यक्ति अपनी आवश्यक सेवाओं का लाभ जैसे पंजीकरण, बिल भुगतान, शिकायत निवारण तथा ऑनलाइन निविदा आदि सेवाओं को अपनी सुविधानुसार इंटरनेट के माध्यम से इंटरनेट के माध्यम से कही पर भी भर सकता है। सरकार द्वारा ई-गवर्नेंस को सुचारू रूप से लागु करने के लिए कई प्रयास किये जा रहे है, जिससे नागरिकों को कम मूल्य से सेवाएं प्राप्त हो सके।

21वी. सदी में आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के द्वारा शासन का तरीका एवं समाज की प्रवृत्ति तेजी से बदल रही है। ई-गवर्नेंस के द्वारा नागरिकों को सरकारी सेवाएं पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। ई-गवर्नेंस न केवल नागरिक सेवाओं के लिए वरन् सार्वजनिक क्षेत्र की दक्षता में वृद्धि करने के लिए भी कार्य करता है। एक अच्छी शासन पद्धति में समान भागीदारी, पारदर्शिता,मानवाधिकार नियम के अनुकुल, समग्रता एवं मध्यरुतता जैसी विशेषताएं होनी चाहिए।

ई-गवर्नेंस को विभिन्न रूप में अलग-अलग उद्धेश्यों के रूप में परिभाषित किया गया है जिनमें से कुछ निम्नांकित है-

- ई-गवर्नेंस को सूचना और संचार प्रधिकरण के माध्यम से जनता और व्यवसाय को कुशल सुविधाजनक एवं पारदर्शी सेवा प्रदान करने के लिए सरकारी परीवर्तन के रूप में परिभाषित किया गया है।

- ई-गवर्नेंस व्यापक रूप् से सरकार के प्रौद्योगिकी परिवर्त को परिभाषित करता है जैसे लागत में कमी आर्थिक विकास, पारदर्शिता सेवा वितरण में सुधार आदि।

इस प्रकार ई-गवर्नेंस मूल रूप से सरकारी कामकाज की प्रक्रिया है जो सरकारी संस्थानों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करता है।

2. शोध पत्र के उद्देश्य :-

1. ई-गवर्नेंस की अवधारणा एवं महत्व का अध्ययन
2.सुशासन में ई-गवर्नेंस की भूमिका का विश्लेषण
3. भारत में ई-गवर्नेंस के विकास का अध्ययन

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी :- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उद्भव ने त्वरित और बेहतर संचार कुशल भंडारण प्रसंस्करण के लिए साधन उपलब्ध कराया है। ई-गवर्नेंस का उपयोग तेजी से और गुणात्मक बेहतर निर्णय लेने, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने, निर्णय प्रक्रिया में व्यापक भागीदारी, नागरिकों को समूह और निजी क्षेत्र की गहरी सहभागिता सुनिक्षित करने के लिए और प्रशासन की सही व्यवस्था के लिए किया जाता है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी एक व्यापक क्षेत्र है। जिसमें सूचना के संचार के लिए हर तरक की तकनीक समाहित होती है। यह वह प्रौद्योगिकी है जो की सूचना के संचार के संचालन उनको एकत्रिकरण और उपयोगी बनाने की योग्यता रखता है तथा संचार के विभिन्न सेवाओं और उनके प्रयोग में सूचना प्रसारण की भूमिका प्रदान करता है। वर्तमान में शिक्षा जगत, स्वास्थ्य, कृषि उद्योग, शासन प्रबंध जैसे क्षेत्रों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास का उल्लेखनीय प्रभाव है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का महत्व-

- सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की सेवा अर्थ तन्त्र का आधार है।
- सूचना सम्प्रेष्ण द्वारा नागरिकों को सशक्त बनाया जा सकता है।
- सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा प्रशासन और सरकार में पारदर्शिता रहती है, जिससे भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलती है।
- सूचना तकनीकि का प्रयोग निति निर्धारण तथा निर्णय लेने में सहायक होता है।
  नये रोजगार के सृजन में सहायक होता है।
- देश के सभी क्षेत्रों में नवाचार एवं विकास सम्पन्न होता है।

अतः सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रशासनिक गतिविधियों को आसान और पारदर्शी तरीके से नियन्त्रित करने में सहायक होता है।

3. भारत में ई-गवर्नेंस:-

भारत में ई-गवर्नेंस की औपचारिक शुरूआत 1970 के दशक में हुई जब राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC) के स्थापना की गई वर्ष 1980 और 1990 के दशक में विभिन्न राज्य सरकारों ने अपने स्तर पर एक ई-गवर्नेंस योजना शुरू की गई। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना देश में सामूहिक रूप् से गवर्नेंस को एकीकृत करने में सहायक होती है। आज इंटरनेट के माध्यम से पुरा देश एक हो रहा है। इस योजना का प्रमुख उद्धेश्य सभी नागरिकों को जन सेवाएं प्रदान करने का है। वर्ष 2000 के दशक में भारत सरकार ने राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना शुरू की जिसमें 31 मिशन मोड प्रोजेक्ट एवं 11 अवयव शामिल है। इस योजना के तहत् दी जाने वाली सेवाओं में प्रबंधकीय ढांचा, भूमि रिकॉर्ड, डिजिटलीकरण, पासपोर्ट सेवाएं और ऑनलाइन टैक्स भुगतान जैसी महत्वपूर्ण सेवाएं शामिल है।

वर्ष 2015 में शुरू हुए डिजिटल इंडिया अभियान में ई-गवर्नेंस को एक नई दिशा प्रदान की है। सरकार की इस पहल का उद्धेश्य नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना तथा सेवाओं को इंटरनेट और मोबाईल फोन के माध्यम से सरल बनाना है। डिजिलॉकर, उमंग एप, आधार का भुगतान और कॉमल सर्विस सेंटर जैसी योजनाएं डिजिटल इंडिया का हिस्सा है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में डिजिटल विभाजन का कम करने के लिए विशेष प्रयास किये गये है। हाल के वर्षों में भारत में ई-गवर्नेंस में उन्नत तकनीक कत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) को अपनाया गया है। कोविड-19 महामारी के दौरान डिजिटल सेवाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जैसे- ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाएं, डिजिटल शिक्षा और अन्य डिजिटल सेवाएं आदि। आज भारत में ई-गवर्नेंस केवल सरकारी सेवाओं की दक्षता बढाने का माध्यम नहीं है बल्कि यह नागरिकों के जीवन में पारदर्शिता, सशक्तिकरण और सामाजिक आर्थिक समावेशन लाने का एक उपकरण भी है।

वर्तमान में भारत में ई-गवर्नेंस शासन के क्षेत्र में प्रौद्यिगिकी और डिजिटल सेवाओं के गहन उपयोग का प्रतीक है। डिजिटल इंडिया के तहत ई-गवर्नेंस को तेजी से बढावा मिला है जिससे नागरीकों और सरकार के बीच संवाद और सेवाओं के आदान-प्रदान में सुविधा हुई है। आज ई-गवर्नेंस ने पारंपरिक कागजी प्रणाली को हटाकर डिजिटल और पारदर्शी प्रक्रियाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। वर्तमान में शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और कृषि जैसे क्षेत्रों में डिजिटलीकरण से नागरीकों को समय और संसाधनों के बचत के साथ-साथ कुशल सेवाए उपलब्ध हुई है। डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के बढते उपयोग ने अर्थव्यवस्था में पारदर्शिता और वित्तिय समावेशन को बढ़ाया है। स्मार्ट सिटी परीयोजना और ई-कोर्ट जैसी सुविधाओं ने शहर और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में ई-गवर्नेंस की पहुच को मजबुत किया है। ई-गवर्नेंस की स्वास्थ्य, ऑनलाइन शिक्षा एवम् राहत वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बावजुद वर्तमान में चुनौतिया बनी हुई है।

4. ई-गवर्नेंस के मुख्य कार्यः- भारत में ई-गवर्नेंस के अन्तर्गत मुख्य कार्यो को प्राथमिकता से लागू किया गया है-

- भ्रष्टाचार मुक्त शासनः- वर्तमान में सरकार ने स्पेक्ट्रम और कई उद्योगों में पारदर्शिता को अपनाया है तथा नए मानक तय किए जिससे सरकार को लाभ प्राप्त हो रहा है।
- आधारभूत संरचना का विकास:- ई-गवर्नेंस के तहत भारत के विकास की रूपरेखा तैयार की गई। जिसमें पावर, रोड, यातायात विकास की सुविधाओं की वृद्धि, हाइवे, रेलवे और पोर्ट सहित विभिन्न मंत्रालयों के बड़े लक्ष्य तय किये गये।
- स्वच्छ भारत अभियान:- ई-गवर्नेंस के द्वारा देश में स्वच्छ भारत अभियान, सेनिटेशन कार्यक्रम और गाँवों में स्वच्छता अभियान चलाये गये इसके लिए देश के सभी नागरीकों को जागरूक किया गया।
- प्रधानमंत्री जनधन योजना:- इस कार्यक्रम का मुख्य उद्धेश्य निम्न वर्गों का बैंक में खाता खुलाकर उन्हे वित्तिय सेवाओं से जोड़ता है और उन्हे आर्थिक तौर पर मजबुत बनाना है, इस हेतु कई नई योजनाओं का शुभारम्भ भी किया गया जिनमें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथाअटल पेंशन योजना भी शामील है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रगति:- ग्रामीण भारत में ई-गवर्नेंस के माध्यम से बैकिंग, कृषि, स्वास्थ और शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन हुआ है। आधार कार्ड जैसी पहचान प्रणाली ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना आसान बना दिया है। भूमि रिकार्ड, डिजिटलीकरण, ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली ने किसानों के लिए कृषि से सम्बन्धित प्रक्रियाओं को आसान और सरल बना दिया है।
- नयी तकनीकों का समावेश:- हाल के वर्षों में क्रत्रिम बुद्धिमत्ता, ब्लॉकचेन, और मशीन लर्निंग जैसी तकनीकों का उपयोग ई-गवर्नेंस के माध्यम से किया जा रहा है। कोविड-19 महामारी की जटिलता के दौरान डिजिटल सेवाओं और ई-गवर्नेंस ने नागरिक सेवाओं को जारी रखने में अहम भूमिका निभाई है।

इन सभी के अलावा प्रधानमंत्री द्वारा आम जनता से सीधे संवाद स्थापित करने के लिए रेडियों पर टॉक शो 'मन की बात' कार्यक्रम आकाशवाणी द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। ऑनलाइन-लाइन वेब आधारित प्रयोगो के माध्यम से स्वयं सेवा प्रक्रिया उपलब्ध कराने की दिशा में धीरे-धीरे बदलाव हो रहा है। ई- गवर्नेंस अवधारणा में चार मुख्य लक्ष्य एवं उद्धेश्य समूह जिनमें सरकार, नागरिक, व्यवसाय और समूहहित पर केन्द्रित है।

5. निष्कर्षः- इस प्रकार ई-गवर्नेंस केवल नागरीकों को सुविधा प्रदान करने का एक माध्यम ही नहीं है वरन् सामाजिक , आर्थिक समावेश और सशक्तिकरण का एक उपलब्ध भी बन चुका है। भारत में ई-गवर्नेंस का वर्तमान परीदृश्य प्रौद्योगिकी और नागरिक सेवा के समन्वय का एक सफल उदाहाण जो शासन का अधिक उन्मुख और बनाने में सहायक है।

सन्दर्भः-

Journal Papers :-

1. चौधरी एस. (2017), ''भारत में ई-गवर्नेंस-डिजिटल समावेश और समाज पर उसके प्रभाव का विश्लेषण,''अन्तर्राष्ट्रीय जनरल ऑफ़ ई-गवर्नेंस रीसर्च, 8(4)333-345
2. Kaur,A. & Soni, A(2018), Digital India: Eavaluation, Progress and challenges. International Journal of Engineering and Technology 10(1) 75-82.

Books :-

1. Bharatnagar,s,(2001), E governee from vision to implementation: A Practical guide with case studies, sage Publications.
2. Mehta(2015), Digital India: vision for a new India National Book trust.